[श्री मीठालाल मीना]

सवाई माधोपुर से निवेदन किया गया, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं है और न सहायता ने के लिए एक पैसा है। सभापति जी, गांव वाले कहते हैं कि हम को खाने को मत दीजिये, रहने के लिये मत दीजिये, लेकिन इन बाढ़ों से हमारे जो तालाब टूट गये हैं, उनको ठीक करने के लिये पैसा दे दीजिये, उनको तत्काल ठीक करा दीजिये ताकि हम आगे की फसल तैयार कर सकें। तालाब ठीक हो जायेंगे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि तालाबों की तत्काल मरम्मत के लिये कोई सहायता नहीं दी जा रही है। पानी बरस रहा है और तालाबों से हो कर निकल रहा है, उनको बन्द नहीं किया जा सकता है। सारी फसल नष्ट हो गई है, बीमारी फैलने की आशंका है— किसी भी तरह का कोई इन्तजाम हां पर नहीं है। यह वह जिला है, जिसको केन्द्र सरकार ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर रखा है, लेकिन उसके लिये केन्द्र सरकार कुछ नही कर रही है। मेरा निवेदन है कि देश में बड़े बड़े बांधों के साथ साथ छोटे छोटे बांधों के लिये भी योजना होनी चाहिये, एक दूसरी नदियों को नहरों द्वारा जोड़ा जाय ताकि इस प्रकार की परिस्थितियों पर कन्ट्रोल किया जा सके।

अन्त में एक बात कह कर खत्म करता हूं—सवाई माधोपुर जिले को अलग से सहायता दीजिये, जिससे कि वहां लोगों को सान्त्वना मिल सके। उन के मकानों के लिए सहायता दीजिये, तालाबों को ठीक करने के लिये तत्काल बिना किसी रुकावट के पैसा पहुंचाइये जिससे कि वे तालाब ठीक हो सकें और वे अगली फसल के लिए व्यवस्था कर सकें।

18.05 hrs.

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 784 Re. DECONTROL OF SUGAR

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): Sir, during the course of supplementary questions by Shri V. **Krishnamoorthy on Starred Question** No. 784 answered on the 28th August, 1969 in this House I had stated that there could not be any permission to pay below the minimum price of sugarcane and that no body could permit that. The fact, however, is as follows:—

The Government of Tamil Nadu had made a specific representation to the Central Government in the 1st week of July, 1969 *i.e.* at the fag end of the crushing season that some unregistered sugarcane was lying in the areas of some sugar factories in the State, which was drying up and that the sugar factories were not prepared to crush it at the prevailing rate of cane price on account of very low recovery likely to be obtained therefrom. The State Government requested that they might be permitted to allow a rebate in the minimum price of sugarcane. The State Government also reported that the cane growers were finding it difficult to dispose of the cane. The Central Government agreed with the proposal of the State Government, on the specific condition that there should be an agreement between the cane growers and the sugar factories in this regard and that the rebate should be calculated with reference to the estimated fall in recovery of sugar from such sugarcane. The Government of India Notification No. GSR 1813|Ess. Com| Sugarcane, dated the 4th October, 1968 provides that the Central Government or with the approval of the Central Government, the State Government or any officer or authority of **the Central or State Governments may** allow a suitable rebate in the minimum price for any valid reason to be specified by the said Government, officer or authority.